

भारत सरकार  
जनजातीय कार्य मंत्रालय  
लोक सभा  
तारांकित प्रश्न संख्या- \*67  
उत्तर देने की तारीख- 04/12/2025

**पीएम-जनमन का कार्यान्वयन**

\*67. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2023-24 से 2025-26 के लिए प्रधान मंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान (पीएम-जनमन) के अंतर्गत वर्ष-वार लक्ष्य निर्धारित किए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पीएम-जनमन के अंतर्गत गैर-विद्यतीकृत घरों के विद्यतीकरण और मोबाइल अथवा दूरसंचार कनेक्टिविटी से संबंधित कार्यों सहित 4जी या 5जी प्रौद्योगिकी टावर लगाने की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) महाराष्ट्र में वर्ष 2023-24 से आज तक पीएम-जनमन के अंतर्गत स्वीकृत, चल रही और पूरी की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है?

**उत्तर**

जनजातीय कार्य मंत्री  
(श्री जुएल ओराम)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख गया है।

\*\*\*\*

श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर द्वारा "पीएम-जनमन का कार्यान्वयन" के संबंध में दिनांक 04.12.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या \*67 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): प्रधानमंत्री जनजाति न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) के उद्देश्यों को 9 संबंधित मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 11 उपायों के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। मिशन को 2023 से 2026 की अवधि के लिए अनुमोदन दिया गया है और मिशन लक्ष्य, मंत्रालय-वार, **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ख): अभियान के तहत, शुरुआत से लेकर अब तक अविद्युतीकृत घरों के विद्युतीकरण और मोबाइल अथवा दूरसंचार सम्पर्क (कनेक्टिविटी) के संबंध में हुई प्रगति **अनुलग्नक-II** में दी गई है।

(ग): अभियान के तहत, महाराष्ट्र राज्य में इसके शुरुआत से लेकर अब तक हुई प्रगति **अनुलग्नक-III** में दी गई है।

श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर द्वारा "पीएम-जनमन का कार्यान्वयन" के संबंध में दिनांक 04.12.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या \*67 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पीएम-जनमन के तहत लक्ष्य

मंत्रालय का नाम	गतिविधि	मिशन लक्ष्य (2023-2026)
ग्रामीण विकास मंत्रालय	पक्के घरों का प्रावधान	4.90 लाख घर
	संपर्क सड़कें	8000 किमी सड़क
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	सचल औषधालय इकाई	1000 एमएमयू (733 एमएमयू सभी को कवर करने के लिए पर्याप्त)
जल शक्ति मंत्रालय	पाइप से जलापूर्ति	19375 गांव
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण और संचालन	2500
शिक्षा मंत्रालय	छात्रावासों का निर्माण और संचालन	500
विद्युत मंत्रालय	अविद्युतीकृत आवासों का विद्युतीकरण	145083 आवास
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	नवीन सौर ऊर्जा योजना के तहत आवासों को मंजूरी	ऑफ ग्रिड के लिए पात्र लाभार्थियों की पहचान के अनुसार
दूरसंचार मंत्रालय	मोबाइल टावरों की स्थापना	4543 बस्तियों का कवरेज
जनजातीय कार्य मंत्रालय	बहुउद्देशीय केंद्र	1000
	वीडीवीके की स्थापना	500

श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर द्वारा "पीएम-जनमन का कार्यान्वयन" के संबंध में दिनांक 04.12.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या \*67 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अविद्युतीकृत आवासों के विद्युतीकरण और मोबाइल या दूरसंचार संपर्क (कनेक्टिविटी) के संबंध में पीएम-जनमन की प्रगति (24 नवंबर 2025 तक)

मंत्रालय का नाम	गतिविधि	मिशन लक्ष्य (2023-2026)	स्वीकृति विवरण	वास्तविक उपलब्धियाँ
विद्युत मंत्रालय	अविद्युतीकृत आवासों का विद्युतीकरण	145083 आवास	145083 आवास	134102 आवास विद्युतीकृत
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	नवीन सौर ऊर्जा योजना के तहत आवासों को मंजूरी	ऑफ ग्रिड के लिए पात्र लाभार्थियों की पहचान के अनुसार	8911 आवास	5814 आवास विद्युतीकृत
दूरसंचार मंत्रालय	मोबाइल टावरों की स्थापना	4543 बस्तियों का कवरेज	4015 बस्तियों के कवरेज के लिए योजना बनाई	2944 बस्तियाँ कवर की गईं
# मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार				

श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर द्वारा "पीएम-जनमन का कार्यान्वयन" के संबंध में दिनांक 04.12.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या \*67 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

महाराष्ट्र राज्य में पीएम-जनमन की प्रगति (24 नवंबर 2025 तक)

मंत्रालय		
ग्रामीण विकास मंत्रालय	मंजूर किए गए घर (संख्या)	54236
	पूरे हुए घर (संख्या)	13754
ग्रामीण विकास मंत्रालय	मंजूर सड़कें (किमी)	50.14
	पूरी हुई सड़कें (किमी)	-
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	संचालित हुए एमएमयू (संख्या)	84
जल शक्ति मंत्रालय	मंजूर किए गए गाँव (संख्या)	2764
	परिपूरित गाँव (संख्या)	1529
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	मंजूर किए गए एडब्ल्यूसी (संख्या)	178
	संचालित हुए एडब्ल्यूसी (संख्या)	178
शिक्षा मंत्रालय	मंजूर किए गए हॉस्टल (संख्या)	25
	हॉस्टल का काम शुरू हुआ (संख्या)	4
विद्युत मंत्रालय	मंजूर किए गए आवास (संख्या)	9216
	विद्युतीकृत आवास (संख्या)	9216
दूरसंचार मंत्रालय	कवरेज के लिए प्लान की गई बस्तियां (संख्या)	417
	कवर की गई बस्तियां (संख्या)	322
जनजातीय कार्य मंत्रालय	मंजूर एमपीसी (संख्या)	121
	पूरे हुए एमपीसी (संख्या)	62
	मंजूर वीडिवीके (संख्या)	40
	कार्य प्रारम्भ (संख्या)	40

\*\*\*\*\*